



पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आम आदमी के बीच जाकर उनके साथ समय बिताने लगे हैं। इस बात को लेकर इन दिनों वो रोज चर्चा में रहते हैं। राहुल गांधी शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को संबोधित करने जयपुर आये तब यहाँ भी उन्होंने एक ऐसा मौका ढूँढ ही लिया। राहुल गांधी ने महारानी कॉलेज जाकर वहाँ छात्राओं के साथ बातचीत की और फिर एक स्टूडेंट की स्कूटी पर पीछे बैठकर मानसरोवर (जयपुर) स्थित सभास्थल पर पहुँचे। राहुल को अपनी स्कूटी पर पीछे बैठाने वाली स्टूडेंट भी काफी उत्साहित नजर आई।

राज्य सरकार की अपील खारिज

जयपुर 23 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में जल संसाधन विभाग से रिटायर हुए अक्सिस्टेंट इंजीनियर के सेवा परिलाभ पर दिए ब्याज के मामले में राज्य सरकार की ओर से बिना कारण अपील दायर करने पर नाराजगी जताई है। और अदालत ने अपील को फिल्टर बताते हुए राज्य सरकार पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया है। मुख्य न्यायाधीश ए.जी. मसीह व जस्टिस समीर जैन को खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार बिना किसी उचित कारण ही अदालत में अपील दायर कर रही है।

अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले ए.जी.एस.एस. राव को मौखिक तौर पर कहा कि सरकारी अफसरों की हर बात नहीं माननी चाहिए। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के अफसरों ने ही रिटायर हुए कर्मचारी के मामले को जांच में देरी की, जिससे उसे बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पाया।

■ वर्ष 2017 में वॉटर वर्क्स से रिटायर हुए एडव. को सेवा परिलाभ पर ब्याज के मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर अपील की हाई कोर्ट ने फिल्टर बताया और 50,000 रु. का हर्जाना लगाया।

वहीं एकलपीठ के आदेश के खिलाफ व्यर्थ की अपील पेश कर दी, जिससे अदालत में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ रही है।

मामले के अनुसार हरीश कुमार व्यास 30 जून, 2017 को जल संसाधन विभाग से रिटायर हुए थे। उसके खिलाफ किसी मामले में विभागीय जांच चल रही थी। इस जांच को पूरा करने में ही विभाग ने सात साल लगा दिए और यह 9 फरवरी 2021 को पूरी हुई। इसके चलते हरीश कुमार को सेवा परिलाभ के भुगतान में देरी हुई। उसने सेवा परिलाभ दिलवाने के लिए एकलपीठ में याचिका दायर की। जिस पर एकलपीठ ने 30 मार्च 2022 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को उपार्जित अवकाश की राशि देने का निर्देश देते हुए बकाया राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने का आदेश दिए। एकलपीठ के इस आदेश को राज्य सरकार ने बिना उचित कारण ही खंडपीठ में चुनौती दी।

आरक्षण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) विधेयक, जो जल्दबाजी में लाया गया, पारित तो हो गया लेकिन यह किसी को नहीं मालूम कि यह कानून लागू कब होगा। अगर सरकार के कुछ मंत्रियों तथा सांसदों के शब्दों पर यकीन किया जाये, तो यह कानून वर्ष 2039 तक लागू हो पायेगा। सुप्रिया श्रीनाटे ने जानना चाहा कि इस आरक्षण विधेयक पारित करने के लिये संसद का विशेष सत्र बुलाने की सरकार को अचानक ही ऐसी क्या जल्दबाजी थी, जबकि इसे अंतराल में छोड़ दिया जाना था। उन्होंने पूछा कि क्या यह अगले चुनावों में महिलाओं को प्रभावित करने का एक और साधन मात्र नहीं है।

प्रोटोकॉल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, विधायक और कई वी.आई.पी. भी पानी के लिए एक दूसरे को इशारा करते रहे, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई।

राहुल छात्रा की स्कूटी पर बैठकर सभा स्थल पहुंचे

राहुल ने महारानी कॉलेज में मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की

जयपुर 23 सितंबर (का.प्र.) कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी शनिवार को प्रदेश के सबसे बड़े महिला महाविद्यालय, महारानी कॉलेज पहुंचे। पहले तो यहाँ उन्होंने मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की और फिर एक छात्रा के साथ स्कूटी पर बैठकर महारानी कॉलेज से मानसरोवर सभा स्थल के लिए रवाना हुए।

इससे पहले उन्होंने कॉलेज में छात्राओं से संवाद किया। राहुल ने यहाँ आने पर खुशी जताते हुए कहा कि, वो कई सारे शैक्षणिक संस्थानों में जा चुके हैं, लेकिन महारानी कॉलेज उन बेस्ट इन्स्टिट्यूट्स में से एक है, जहाँ वो गए हैं। आगे राहुल ने कहा कि, युवाओं के

- महारानी कॉलेज से राहुल गांधी हैलमेट लगाकर स्कूटी पर बैठकर मानसरोवर पहुंचे।
- राहुल ने महारानी कॉलेज में छात्राओं से बात की और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की।

लिफ जो जरूरी है, उस विषय पर बात होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर भी खुलकर अपने विचार रखे।

अन्य कार्यक्रमों से पहले महारानी कॉलेज पहुंचे राहुल गांधी ने लाइव्री विजिट की और फिर इसके बाद मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की। यहाँ से मानसरोवर स्थित सभा स्थल तक जब हैलमेट पहने राहुल गांधी एक छात्रा की

स्कूटी पर बैठकर गए, उस समय उनकी सिक्यूरिटी के लोग मुख्य मार्ग टॉक रोड पर दौड़ते नजर आए। राहुल गांधी को अपनी स्कूटी पर पीछे बैठाने वाली छात्रा भी खासा उत्साहित लग रही थी। मानसरोवर में सभा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे और राहुल गांधी सेंट्रल पार्क गए, जहाँ उन्होंने गांधी वाटिका का लोकार्पण किया।

अब इंदिरा गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गिरिराज सिंह, जिन्होंने 1, सफदरजंग को सरकार को वापस किये जाने की मांग की है, ने इस तथ्य को अपने तर्क को आधार बनाया है-राष्ट्रीय राजधानी में इस समय सभी 15 पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिये एक स्मारक है।

सिंह ने एक्स पर कहा, "मैं मांग करता हूँ कि सारे भारत में बिखरे सभी राजवंशीय भवनों का आकलन किया जाये तथा इनकी तर्काधारित समीक्षा की जाये। इसका शुभारंभ करते हुये, 1, सफदरजंग कॉम्प्लेक्स को तुरंत भारत सरकार को वापस किया जाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार के कार्यकाल में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि भविष्य में कोई भी सरकारी बंगला राजनेताओं के स्मारक के रूप में तब्दील नहीं किया जायेगा। वर्ष 2014 में, नरेन्द्र मोदी सरकार ने भी इस नीतिगत निर्णय को दोहरा दिया था तथा इसके साथ ही, यह भी संकल्प लिया था कि, महात्मा गांधी के अलावा, किसी भी राजनेता की जयंती

■ वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था कि, महात्मा गांधी के अलावा किसी भी नेता की जयंती या पुण्यतिथि नहीं मनाई जायेगी।

का जन्मदिन एवं पुण्यतिथि अब सरकार द्वारा नहीं मनाए जायेंगे।

वर्ष 2018, बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में अपना 13 ए. माल एवेंयू निवास खाली किया था जिसे उन्होंने बसपा के संस्थापक काशीराम का स्मारक घोषित कर दिया था।

उन्होंने अपना आवास खाली करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश की अनुपालना में लिया था, जिसमें कहा गया था कि सभी पूर्व मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास खाली कर दें।

रूस, अमेरिका और चीन नई न्यूक्लियर वैपन परीक्षण साइट ढूँढ रहे हैं

नई दिल्ली, 23 सितम्बर। रूस, अमेरिका और चीन की न्यूक्लियर साइट को लेकर बड़ा दावा किया गया है। तीनों देशों ने अपने परमाणु साइट के पास नई फैसिलिटी तैयार की हैं। साथ ही हाल के वर्षों में नई सुरंगें भी खोदी गई हैं। सी.एन.एन. की ओर जारी सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से यह बात कही जा रही है। यह खबर ऐसे समय सामने आई है जब इन तीनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है और ये सभी बड़ी परमाणु शक्ति वाले देश हैं। क्या रूस, अमेरिका और चीन जल्द ही कोई न्यूक्लियर टैस्ट करने वाले हैं? जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें तो इसके सबूत नहीं मिलते हैं। एक्सपर्ट ने कहा, यह जरूर साबित होता है कि तीनों ही देशों की न्यूक्लियर साइट्स पहले की तुलना में बड़ी हो गई हैं।

बता दें कि चीन की न्यूक्लियर साइट शिनजियांग के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में है। रूस की यह साइट आर्कटिक

खालिस्तानी आतंकी पत्र और निज़र की सभी सम्पत्ति एन.आई.ए ने जब्त की

जालंधर में आतंकी के घर के बाहर एन.आई.ए. ने नोटिस चिपका दिया है कि, अब यह सम्पत्ति केन्द्र सरकार की है

जालंधर, 23 सितंबर (वार्ता)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत चंडीगढ़ और अमृतसर में प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एस.एफ.जे.) संगठन के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

एन.आई.ए. मोहाली अदालत के आदेश पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज़र के घर पर भी कार्रवाई हुई है। जालंधर जिले के भासिंहपुरा गांव में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज़र के घर के बाहर संपत्ति जत्ती का नोटिस चिपका दिया है।

चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में पन्नू के आवास के बाहर चिपकाए गए संपत्ति जत्ती नोटिस में लिखा है, मकान नंबर 2033 का 1/4 हिस्सा सेक्टर 15-सी, चंडीगढ़, गुरपतवंत सिंह पन्नू के स्वामित्व में, जो एन.आई.ए. मामले के अंतर्गत 19/2020/एन.आई.ए./डी.एल.आई

■ गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका स्थित अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस (एफ.एस.जे.) के संस्थापकों में से एक हैं और अमेरिका, कैनडा और ब्रिटेन में सिखों के लिए एक अलग राज्य, जिसे वे खालिस्तान कहते हैं, की सक्रिय रूप से पैरवी करते हैं।

में 'घोषित अपराधी' है, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 33 (5) के तहत राज्य द्वारा जब्त कर लिया गया है।

इसी तरह का नोटिस अमृतसर में गुरपतवंत सिंह पन्नू के पैतृक गांव खानकोट में उनकी कृषि भूमि पर भी लगाया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2020 में दर्ज एक आतंकवादी मामले के संबंध में गांव में पन्नू की 46 कनाल कृषि भूमि जब्त कर ली है। पन्नू के पिता मोहिंदर सिंह पन्नू विभाजन से पहले तरनतारन के पट्टी उपमंडल के नाथु चक गांव के निवासी थे। विभाजन के बाद परिवार अमृतसर के खानकोट गांव में स्थानांतरित हो गया।

गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका स्थित अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस (एफ.एस.जे.) के संस्थापकों में से एक हैं और अमेरिका, कैनडा और ब्रिटेन में सिखों के लिए एक अलग राज्य, जिसे वे खालिस्तान कहते हैं, की सक्रिय रूप से पैरवी करते हैं। जुलाई 2020 में, पन्नू को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी नामित किया गया था और दो महीने बाद, सरकार ने कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 51 ए के तहत उसकी संपत्तियों की कुर्क का आदेश दिया।

पन्नू भारत के खिलाफ अभियान चला रहा है और अपने गृह राज्य पंजाब में सिख युवाओं को आतंकवाद में

शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। वह तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह के एक प्रमुख आयोजक रहे हैं, जिन्होंने दुनिया भर के सिखों को इस बात पर मतदान करने के लिए आमंत्रित किया कि क्या पंजाब को धर्म के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहिए। उन्होंने कैनडा स्थित हरदीप सिंह निज़र के साथ भी मिलकर काम किया, जिनकी हत्या कैनडा और नई दिल्ली के बीच राजनयिक गतिरोध के केंद्र में रही है।

कैनडा में बढ़ रही खालिस्तानी गतिविधियों के पीछे गुरपतवंत सिंह पन्नू का हाथ है। यह वही पन्नू है, जो अक्सर सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बातें करता है। कैनडा मामले में भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत पन्नू ने एक वीडियो जारी कर भारतीय मूल के हिंदुओं को धमकी दी थी। इसके साथ ही, उनसे देश छोड़ने के लिए भी कहा था।

प्र.मंत्री 9 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) की ओर से बताया गया है कि नई ट्रेन्स यात्रियों को विषय स्तरीय अनुभव देगी और पर्यटन को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री इन रूट्स की कई नई भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स की शुरुआत करेंगे:-

1. उदयपुर-जयपुर
2. तिरुनेलवेलि-मदुरै-चैन्नै
3. हैदराबाद-बंगलूरु
4. विजयवाड़ा-चैन्नै (वाया रेनिगुन्टा)
5. पटना-हावड़ा
6. कसारागोड-तिरुवनन्तपुरम
7. राउरकेला-भुवनेश्वर-पुरी
8. रांची-हावड़ा और
9. जामनगर-अहमदाबाद

पी.एम.ओ. की ओर से आगे बताया गया कि इन नई ट्रेन्स से देश में रेल सेवाओं के एक नए सोपान की शुरुआत होगी। इन ट्रेन्स में क्वच तकनीकी सहित विषय के अत्याधुनिक साधन और निरव्यव स्तरीय सुविधाएं हैं। ये साधारणजन, पेशेवरों, कारोबारियों, छात्र वरिष्ठ और पर्यटकों को यात्रा का आधुनिक गतिशील एवं सहज साधन उपलब्ध करवाने की दिशा में एक कदम है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी में ए.बी.वी.पी. की जीत का परचम लहराया

ए.बी.वी.पी. ने अध्यक्ष समेत तीन पदों पर कब्जा किया, एन.एस.यू.आई. को एक सीट मिली

नई दिल्ली, 23 सितम्बर। दिल्ली विश्वविद्यालय में कोरोना महामारी की वजह से तीन साल बाद हुए छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ए.बी.वी.पी.) ने अध्यक्ष पद समेत तीन सीटों पर दर्ज की है जबकि नेशनल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया (एन.एस.यू.आई.) ने उपाध्यक्ष पद पर जीत का परचम लहराया है। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर ए.बी.वी.पी. के तृपार डेवा ने एन.एस.यू.आई. के हितेश गुलिया को 3,115 मतां से पराजित किया। अध्यक्ष पद पर ए.बी.वी.पी. के तुपार डेवा को 23,460 मत मिले हैं जबकि अध्यक्ष पद पर एन.एस.यू.आई. हितेश गुलिया को 20,345 वोट मिले हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एन.एस.यू.आई. के अभि दहिया को

- दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में हर बार अच्छा प्रदर्शन करने वाले वामपंथी छात्रों के संगठन आइसा को इस बार एक भी सीट नहीं मिली।
- आइसा की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार को मात्र तीन हजार वोट ही हासिल हुये।

22,331 वोट और ए.बी.वी.पी. (साल 2019) की तुलना में करीब 2,10 फीसदी अधिक थे। पिछले चुनाव यानी साल 2019 के चुनाव में 39.90 फीसदी वोट पड़े। तीन साल हुए इस चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सुचुक्त सचिव पदों के लिए 24 प्रत्याशी मैदान में थे। डीयू के 52 कॉलेजों और केंद्रों पर वोट डाले गए थे।

कॉलेजों में बनाए गए पोलिंग स्टेशन पर तय समय पर सुबह 8.30 से वोटिंग शुरू हुई जो कि दोपहर एक बजे समाप्त हुई।

डू चुनावों में शुक्रवार को 42 फीसदी वोट पड़े जो पिछले चुनाव

वसंधुरा राजे ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) से खिलेंगे। अब मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाएं, जहां हमारी जेटियां बेखौफ अपना बचपन जी सकें। हमारी बहनें बिना किसी बाधा के अपने सपने पूरे कर सकें। हमारी माताएं सम्मान के साथ सिर ऊँचा करके चल सकें।

दिल्ली में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के निवासियों को उमस भरे मौसम में इस बारिश से राहत मिली। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार सुबह बताया कि "दिल्ली और एन.सी.आर. के सीमावर्ती क्षेत्रों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी तथा बिजली चमकने के साथ आंधी-तूफान और मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा था कि दिल्ली के ही हिण्डन एयर फोर्स स्टेशन, गाज़ियाबाद, इन्दिरापुरम, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानसरोवर, सोनीपत और बल्लभगढ़ आदि एन.सी.आर. क्षेत्रों से तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है।

'अगर अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) एक आतंकवादी था और एक वर्ष पूर्व एक प्रतिद्वंदी सिख नेता की हुई कथित हत्या में शामिल था।

वास्तव में टूंडो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह एक आतंकवादी को क्यों पनाह दिए हुए हैं।

इस बीच, इसके बावजूद कि टूंडो ने "फावड आइडल" सिक्कीरिटी एमिनीट ग्रुप के सदस्यों द्वारा भारत की तुरन्त एवं स्पष्ट निन्दा किये जाने का आह्वान किया है, इस प्रकार का कोई भी बयान सामने नहीं आया। जहाँ अमेरिका ने इस पर किसी प्रकार की अधिकृत टिप्पणी नहीं की है, कैनडा में अमेरिका के राजदूत ने कहा कि कुछ खुशियां शेयरिंग हुई हैं।

पूरा विवाद एवं दावे तथा कल्ल के दावे पूरे दोषाधारण के पीछे के कारणों के कई स्तरों की ओर संकेत कर रहे हैं। बताया जाता है कि जस्टिस टूंडो राजनैतिक दबाव में है तथा इससे उसके द्वारा एकाएक किये गये रहस्योद्घाटनों का आंशिक स्पष्टीकरण भी मिलता है। इसके परिणामस्वरूप वे हाई फैक्ट्स को लेकर आगे नहीं आ रहे हैं।